बिहार के गांवों को पेय जल

4145. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के छः लाख गांवों में ऐसे गांव कितने हैं जिनमें और यहां तक कि जिनमें शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं है ; इन गांवों में पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ; इस सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति क्या है ;

(ख) बिहार में इस तरह के गांव कितने हैं तथा विशेषकर छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी गांवों की स्थिति क्या है और उनकी समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या यह सच है कि पेयजल की कमी का सबसे अधिक प्रभाव आदिवासियों और हरिजनों पर पड़ा है और पेयजल के अभाव में वे रोगी भी अधिक होते हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) उन समस्याग्रस्त गांवों, जिनमें 1-8-1987 की स्थिति के अनुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिये) सातवीं योजना के अन्त तक बाकी सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल की सुविधायें उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है ।

(ख) 1-8-1987 की स्थिति के अनुसार, बिहार में ऐसे 4334 समस्याग्रस्त गांव हैं जिनमें स्वच्छ पेयजल सुविधायें नहीं हैं । समस्याग्रस्त गांवों को जिलावार कवर करने की निगरानी केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की जा रही है । ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल की सप्लाई का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं बनाती है और उन्हें निष्पादित करती हैं । केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है ।

(ग) जी नहीं । त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों जैसे समाज के गरीब लोगों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें जल सप्लाई सुविधायें समान रूप से मुहैया कराई जा रही हैं । राज्यों को सलाह दी गई है कि योजनाएं बनाते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों को कवर करने में सबसे पहले तरजीह दी जानी चाहिए ।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1-8-1987 को शेष रहे समस्याग्रस्त गांव
1.	आन्ध्र प्रदेश	3498
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	3539
4.	बिहार	4334
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	3913
7.	हरियाणा	1132
8.	हिमाचल प्रदेश	2436
9.	जम्मू व कश्मीर	2030
10.	कर्नाटक	2743
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	10364
13.	महाराष्ट्र	36528
14.	मणिपुर	481
15.	मेघालय	2831
16.	मिजोरम	456

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1.8.1987 के शेष रहे समस्या ग्रस्त गाँव
17.	नागालैण्ड	506
18.	उड़ीसा	9069
19.	पंजाब	8428
20.	राजस्थान	2513
21.	सिक्किम	30
22.	तमिलनाडु	--
23.	त्रिपुरा	1617
24.	उत्तर प्रदेश	20290
25.	पश्चिम बंगाल	7326
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	--
27.	दमन व दीव	--
28.	लक्षद्वीप	--
29.	पाण्डिचेरी	19
	योग :	124083

Position of irrigation projects

4146. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the number of irrigation projects completed during the last five years, State-wise;

(b) the number of irrigation projects still behind the scheduled time of completion, State-wise; and

(c) the number of projects abandoned, State-wise?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) The aspect of completion of projects is assessed at the end of each Plan. State-wise information regarding the major and medium irrigation projects completed during the Sixth Plan period (1980-85) is given in the Statement enclosed. (*See* below). Such information relating to minor schemes is not maintained at the Centre.

(b) Most of the 614 on-going major and medium projects are running behind schedule.

(c) There are no reports from State Governments regarding such abandonment of projects.

Statement

Sl. No.	Name of State	Major	Medium
1	Andhra Pradesh	1	..
2	Arunachal Pradesh	..	..
3	Assam	..	1
4	Bihar	3	26
5	Goa	..	..
6	Gujarat	4	12
7	Haryana	2	3
8	Himachal Pradesh	—	2
9	Jammu & Kashmir	..	..
10	Karnataka	..	7
11	Kerala	..	..
12	Madhya Pradesh	6	37
13	Maharashtra	5	44
14	Manipur	..	..
15	Meghalaya	..	..
16	Mizoram	..	..
17	Nagaland	..	..
18	Orissa	2	7
19	Punjab	3	..
20	Rajasthan	..	..
21	Sikkim	..	..
22	Tamil Nadu	3	13
23	Tripura	..	..
24	Uttar Pradesh	6	6
25	West Bengal	1	1
	TOTAL (STATES)	36	159

Transfer of property and land in Delhi

4147. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that transfer of property and land in Delhi on General power of attorney is causing a loss of crores of rupees to the Government and it is also generating black money;

(b) if so, whether Government propose to impose a ban on the sale and transfer of interest in land and property to check this menace in view of the resolution adopted by Delhi Metropolitan Council in Delhi on 22nd Jouly, 1987;

(c) whether Government propose to permit the registration of sale deeds for the transfer/sales of land and property in Delhi, if not, the reasons therefor; and

(d) if not, what remedial measures Government propose to take to check this irregular activity?